



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III - खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2007/श्रावण 25, 1929

No. 164]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2007/SRAVANA 25, 1929

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 14 अगस्त, 2007

सं. टीएएमपी/47/2006-वीपीआरसीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से विशाखापत्तनम पत्तन को जोड़ने वाले नवनिर्मित जोड़ मार्ग/उड़्डान पुलों के लिए सड़क कर निर्धारण हेतु विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव को एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/47/2006-वीपीआरसीएल

विशाखापत्तनम पत्तन मार्ग कम्पनी लिमिटेड

—आवेदक

आदेश

(अगस्त 2007 के 7वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापत्तनम पत्तन को राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से जोड़ने वाले नवनिर्मित जोड़मार्ग/उड़्डान पुलों के लिए सड़क-कर निर्धारण करने हेतु विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड से 8 नवम्बर, 2006 को प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. दिसम्बर 2000 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (रा.रा.वि.परि.) चरण-I में अन्य बातों के साथ महापत्तनों को सड़क मार्गों से जोड़ना भी शामिल है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा विशाखापत्तनम् पत्तन से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 तक योजकता विकसित करने के लिए पत्तन-मार्ग योजकता परियोजना हाथ में ली गई है। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास और भा.रा.रा.प्राधि. के संयुक्त उपक्रम के रूप में एक विशेष प्रयोजन निकाय (एसपीवी) विशाखापत्तनम् पत्तन रोड कम्पनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) की दिनांक 26 दिसम्बर 2000 को स्थापना की गई थी।

2.2. कथित पत्तन सड़क योजकता परियोजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 8 नवम्बर 2006 को विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) और वीपीआरसीएल ने एक रियायती करार (कन्सेशन एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए थे। इस रियायती करार के अनुसार वीपीआरसीएल सड़क योजकता (सड़क मार्ग) के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण का काम हाथ में लेगा और इसके साथ ही उसे इस परियोजना का उपयोग करने वालों से उसका शुल्क (टोल) मांगने / प्राप्त करने तथा विनियोजित करने का एक मात्र और अनन्य अधिकार होगा।

2.3. प्रस्ताव की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :-

- (i) सड़क योजकता परियोजना जून 2002 में आरंभ हुई और इसके दिसम्बर 2006 तक यातायात के लिए खुल जाने की संभावना है।
- (ii) पत्तन योजकता सड़क परियोजना में लगभग 12.5 कि.मीटर में उड़्डान पुल (फ्लाई ओवर) रैम्प और भूमितल पर (निर्मित) सड़क इत्यादि समाहित हैं।
- (iii) वीपीआरसीएल ने बताया है कि परियोजना की कुल लागत, जैसाकि आईडीएफसी द्वारा तैयार रिपोर्ट में बताया गया है, 93.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 114 करोड़ रुपये हो गई है।
- (iv) इस परियोजना के विकास की परिकल्पना पत्तन क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 तक पत्तन यातायात की शीघ्र निकासी हेतु सीधा मार्ग प्रदान करने और सड़कों पर आने वाले रेल्वे क्रॉसिंग की रूकावटों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से जोड़ने वाली वर्तमान सड़कों पर अनुभव की गई यातायात की भीड़भाड़ से रहित निर्बाध यातायात प्रवाह प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। कथित पत्तन योजकता सुविधा शहर के भीतर और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचालित और यह जनता के वाहन संबंधी यातायात तथा पत्तन के कार्गो यातायात की आवश्यकता को भी पूरा करेगी।
- (v) परियोजना के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त मेसर्स आईडीएफसी ने 2003 में, परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने कार / जीप / वैन के लिए रु. 10/-, हल्के भार वाही वाहनों के लिए रु. 20/- बसों / ट्रकों के लिए रु. 40/- और एमए वाहनों के लिए रु. 60/- टोल / सड़क-मार्गशुल्क की सिफारिश की है।
- (vi) भा.रा.रा.प्राधि. ने भी पत्तन योजकता परियोजना पर एक विस्तृत यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की है और विस्तृत गणना और रिपोर्ट के साथ टोल-ढाँचा (टोल का स्वरूप) भी सुझाया है।

2.4. तदनुसार, वीपीआरसीएल द्वारा प्रभारित किए जाने हेतु प्रस्तावित टोल निम्नानुसार है :-

- (i) टोल, निम्नलिखित दो स्थानों पर लगाए जाने के लिए प्रस्तावित है :-
 (क) टोल प्लाजा 1 : राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर अयप्पन मंदिर जंक्शन के निकट मुख्य टोल प्लाजा।
 (ख) टोल प्लाजा 2 : औद्योगिक बाई-पास पर दूसरा टोल-प्लाजा।
- (ii) प्रस्तावित टोल ढांचा और प्रस्तावित रियायत नीचे सारणीबद्ध दिए गए हैं :-
 (क) प्रस्तावित टोल

(रूपयों में)

क्रम सं.	वाहनों का वर्ग / श्रेणी	मुख्य टोल प्लाजा के लिए प्रस्तावित दर	द्वितीयक टोल प्लाजा के लिए प्रस्तावित दर
(i)	कार / जीप / वैन	9	5
(ii)	हल्के भारवाही वाहन (एलसीवी)	17	9
(iii)	ट्रक / बस	33	18
(iv)	एमएवी (3 से 6 धुरियों वाले) / एचसीएम / ईएमई	54	28
(v)	अत्यधिक बड़े आकार के वाहन (सात या उससे अधिक धुरी वाले)	66	35

(ख) प्रस्तावित रियायत :-

क्रम सं.	पास	रियायत
1.	मासिक	माह में 50 एकल यात्राओं के लिए, टोल प्लाजा 1 और 2 पर 50 एकल यात्राओं के लिए अन्यथा देय राशि के एक तिहाई के बराबर।
2.	दैनिक	टोल प्लाजा 1 पर, एक ही दिन में वापसी यात्रा के लिए एकल यात्रा की दर का डेढ़ गुना और टोल प्लाजा 2 पर प्रतिदिन 2 यात्राओं के लिए एकल यात्राओं की दर का डेढ़ गुना।
3.	स्थानीय	कार / जीप / वैन स्थानीय उपयोगकर्ता अर्थात् प्लाजा के 20 कि.मी. के दायरे के भीतर रहने वाले निवासियों के लिए रु. 150/- प्रतिमाह की दर से मासिक पास।

(ग) निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को प्रस्तावित टोल से मुक्त रखने का प्रस्ताव है :-

- भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केन्द्रीय मंत्री, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, मुख्य मंत्री केन्द्रीय एवं राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी एवं विपक्ष के नेता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और राज्य के दौरे पर आए विदेशी अभ्यागतों को सेवा प्रदान कर रहे और उनके साथ चल रहे सरकारी वाहन।
- अर्धसैनिक बलों और पुलिस समेत वर्दी में केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बलों तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी के सरकारी वाहन।
- पूरे देश में (कहीं के भी) सांसद, राज्य विधान परिषद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य, अपने-अपने राज्यों में, जब वाहन में बैठे हों तब संसद या किसी राज्य की विधायिका द्वारा, जैसा भी मामला हो, जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर।
- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे पराक्रमी पुरस्कार विजेताओं से संबंधित वाहन बशर्ते कि ऐसा पुरस्कार विजेता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है।

- सीसी / सीडी नंबर प्लेटों वाले वाहन।
- अम्बुलेंस, अग्निशामक गाड़ियां, और शव-वाहिनी गाड़ियां। और
- राजमार्ग का उसके निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए उपयोग करने वाले व्यक्तियों के वाहन।

नोट: डाक-तार विभाग के वाहन और सरकारी ड्यूटी पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के वाहन छूट-प्राप्त वाहनों के रूप में अर्हक नहीं होंगे।

- (iii) वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्तावित टोल दिसम्बर 2005 के थोक बाजार मूल्य सूचकांक पर आधारित है और उसे थो.मू.सू. के आधार पर प्रतिवर्ष संशोधित किया जाना है।

2.5. वीपीआरसीएल ने प्रस्तावित टोल की गणना का आधार भी प्रस्तुत किया है। हाल ही के यातायात अध्ययनों के आधार पर यह प्रस्तावित टोल की वसूली से वर्ष 2006-07 में 6.12 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद की है।

3.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्तावित टोल ढांचे की गणना के आधार के साथ वीपीआरसीएल का प्रस्ताव वि.प.न्यास और सम्बद्ध एसोसिएशनों, पब्लिक यूटीलिटी आपरेटरों, सांविधिक प्राधिकारियों समेत प्रमुख उपयोगकर्ताओं को, उनका अभिमत जानने के लिए अग्रेषित कर दिया गया था।

3.2. सम्बद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिमत वीपीआरसीएल को प्रतिपूरक सूचना के रूप में उसके अभिमत के लिए अग्रेषित किया गया था। तथापि वीपीआरसीएल उपयोगकर्ताओं के अभिमत पर अपना कोई अभिमत अभी तक नहीं दिया है।

4.1. प्रकरण को नव परामर्श प्रक्रिया पर लिया जा रहा था, वीपीआरसीएल ने प्राधिकरण से प्रस्तावित टोल अनुमोदित करने का अनुरोध किया था क्योंकि वह सड़क योजकता प्रकल्प को यातायात के लिए 1 दिसम्बर 2006 से खोलने की योजना बना रहा था। इसने, आरंभ में अपने प्रस्तावित टोल ढांचे में बहुत थोड़ा-सा समायोजन प्रस्तावित किया था। वाहनों की छूट-श्रेणी में कोई परिवर्तन / संशोधन प्रस्तावित नहीं था। वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तावित संशोधित टोल ढांचा नीचे सारणीबद्ध दिया गया है :-

1(क) अयप्पन मंदिर के पास मुख्य टोल प्लाजा पर टोल

(रुपयों में)

क्रम सं.	वाहनों का वर्ग / श्रेणी	एकल यात्रा दर	24 घंटे तक वैध वापसी यात्रा -दर
(i)	कार / जीप / वैन	10	15
(ii)	हल्के भारवाही वाहन (एलसीवी)	15	25
(iii)	ट्रक / बस	35	55
(iv)	एमएवी (3 से 6 धुरियों वाले) / एचसीएम / ईएमई	55	85
(v)	अत्यधिक आकार वाले (सात या उससे अधिक धुरीवाले) वाहन	65	100

1(ख) कॉन्वेंट जंक्शन और रा.रा.-5 पर अयप्पन मंदिर के बीच (अयप्पन मंदिर के पास मुख्य टोल प्लाजा पर) स्थानीय यातायात / बारम्बार यात्रियों को रियायतों के साथ टोल।

(रुपयों में)

क्र. सं.	पास	कार / जीप / वैन	हल्के भार वाही वाहन	ट्रक / बस	एमएवी (3 से 6 धुरी वाले) / एचसीएल / ईएमई	अत्यधिक आकार वाले (सात या अधिक धुरी वाले) वाहन
1.	मासिक पास (एक माह में 50 एकल यात्राओं के लिए अन्य या देय राशि के 1/3 के बराबर छूट के साथ)	335	500	1165	1835	2165
2.	दैनिक पास एक ही दिन में वापसी यात्रा एकल यात्रा की दर का 1.5 गुना	15	25	55	85	100
3.	माह के लिए स्थानीय पास (टोल प्लाजा के 20 कि.मी. के दायरे के निवासियों के लिए आवासीय सबूत और वाहन का स्वामित्व प्रमाण प्रस्तुत करने पर)	150	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

II.(क). 'Y' जंक्शन के पास सैकेन्दरी टोल प्लाजा के लिए टोल

(रुपयों में)

क्रम सं.	वाहनों का वर्ग / श्रेणी	एकल यात्रा दर	24 घंटे तक वैध वापसी यात्रा - दर
(i)	कार / जीप / वैन	5	10
(ii)	हल्के भारवाही वाहन (एलसीवी)	10	15
(iii)	ट्रक / बस	20	30
(iv)	एमएवी (3 से 6 धुरियों वाले) / एचसीएम / ईएमई	30	45
(v)	अत्यधिक आकार वाले (सात या उससे अधिक धुरीवाले) वाहन	35	55

II.(ख). कॉन्वेंट जंक्शन और 'Y' जंक्शन के बीच ('Y' जंक्शन के पास सैकेन्दरी टोल प्लाजा के लिए) स्थानीय यातायात / बारम्बार यात्रियों को रियायतों के साथ टोल।

(रुपयों में)

क्र. सं.	पास	कार / जीप / वैन	हल्के भार वाही वाहन	ट्रक / बस	एमएवी (3 से 6 धुरी वाले) / एचसीएल / ईएमई	अत्यधिक आकार वाले (सात या अधिक धुरी वाले) वाहन
1.	मासिक पास (एक माह में 50 एकल यात्राओं के लिए अन्य या देय राशि के 1/3 के बराबर छूट के साथ)	165	335	665	1000	1165
2.	दैनिक पास (एक ही दिन में दो यात्राओं के लिए एकल यात्रा की दर का 1.50 गुना)	10	15	30	45	55
3.	माह के लिए स्थानीय पास (टोल प्लाजा के 20 कि.मी. के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए निवासी होने का प्रमाण और वाहन का स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने पर)	150	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3524 45/07-2

4.2. वीपीटी और वीपीआरसीएल ने तदर्थ आधार पर लगाए जाने वाले टोल के संबंध में, 17 नवम्बर 2006 को प्रासंगिक उपयोगकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन कर विचार विमर्श किया। 17 नवम्बर 2006 को हुई बैठक में विचार विमर्श को नोट किया गया। वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तुत यह नोट दर्शाता है कि प्रासंगिक उपयोगकर्ताओं ने प्रस्तावित दरों को प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित किए जाने तक तदर्थ आधार पर लगाने के लिए, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है।

4.3. चूंकि परियोजना को यातायात के लिए 1 दिसम्बर 2006 से खोल देने का प्रस्ताव था, एक प्रशुल्क व्यवस्था को कायम करना आवश्यक हो गया था ताकि वीपीआरसीएल सुविधाओं को प्रचालित कर सके। जैसाकि प्रस्तावित तदर्थ दरें परस्पर सहमत दरें थीं, 6 माह की अवधि के लिए एक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में प्रस्तावित तदर्थ दरों को अनुमोदित करते हुए इस प्राधिकरण ने एक आदेश सं. टीएएमपी / 47/2006-वीपीआरसीएल, 28 नवम्बर 2006 को पारित किया। यह आदेश राजपत्र सं. 177 के माध्यम से भारत का राजपत्र में 1 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित किया गया।

5.1. तदनन्तर, वीपीआरसीएल ने इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तदर्थ मासिक पास प्रणाली के संदर्भ से उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों का वर्णन किया। चूंकि अनेक उपयोगकर्ताओं की एक-एक दिन में अनेक चक्कर लगाने पड़ते थे, ये मासिक पास 4 से 5 दिन की अल्पावधि में ही हो जाते थे। 50 सीमित यात्राओं के साथ जारी किए गए मासिक पास पूरे एक माह के लिए अपर्याप्त पाए गए। पत्तन उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, वीपीटी ने वीपीआरसीएल को असीमित यात्राओं के लिए पास जारी करने की सलाह दी। वीपीटी ने वीपीआरसीएल को, ड्यूटी पर सरकारी वाहनों को भी टोल-मुक्त करने की सलाह दी।

5.2. इस पृष्ठभूमि में, वीपीआरसीएल ने असीमित यात्राओं के लिए दैनिक / मासिक पास हेतु अलग दरें आरंभ करने का प्रस्ताव किया। एकल यात्रा के लिए अनुमोदित वर्तमान तदर्थ दर को आधार लिया गया है और असीमित यात्राओं हेतु दैनिक पास के लिए 6 यात्राओं की प्रस्तावित दर की गणना के लिए लागू की गयी है। इसी प्रकार, मासिक पास के लिए इसी सूत्र को 30 दिन प्रतिमाह के लिए लागू किया गया है। तदनुसार, असीमित यात्राओं हेतु पास जारी करने के लिए वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तावित टोल ढांचा नीचे सारणीरूप में दिया गया है :

अयप्पन मंदिर के पास मुख्य टोल प्लाजा पर

(रुपयों में)

क्रम सं.	पास	कार / जीप / वैन	हल्के भार वाही वाहन	ट्रक / बस	एमएवी (3 से 6 धुरी वाले) / एचसीएल / ईएमई	अत्यधिक आकार वाले (सात या अधिक धुरी वाले) वाहन
1.	दैनिक पास (असीमित यात्राएं)	60	90	210	330	390
2.	मासिक पास (असीमित यात्राएं)	1800	2700	6300	9900	11700

'Y' जंक्शन के पास सैकेन्डरी टोल प्लाजा पर

(रुपयों में)

क्रम सं.	पास	कार / जीप / वैन	हल्के भार वाही वाहन	ट्रक / बस	एमएवी (3 से 6 धुरी वाले) / एचसीएल / ईएमई	अत्यधिक आकार वाले (सात या अधिक धुरी वाले) वाहन
4(क)	दैनिक पास (असीमित यात्राएं)	30	60	120	180	210
4(ख)	मासिक पास (असीमित यात्राएं)	900	1800	3600	5400	6300

5.3. वाहनों की टोल-मुक्त श्रेणी की वर्तमान सूची के अतिरिक्त वीपीआरसीएल ने, भा.रा.रा.प्राधि. की संशोधित नीति लागू होने तक, ड्यूटी पर सरकारी वाहनों को टोल से छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसने यह भी उल्लेख किया है कि सैकेन्डरी टोल प्लाजा में, दैनिक पास दो यात्राओं के लिए है न कि वापसी यात्रा के लिए जैसा कि 1 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित अन्तरिम प्रशुल्क में उल्लेख किया गया है और इसलिए विवरण को तदनुसार ठीक किए जाने की आवश्यकता है।

5.4. असीमित यात्राओं के लिए पास जारी करने हेतु इसके प्रस्ताव के संदर्भ में वीपीआरसीएल को कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :-

- (i) भा.रा.रा.प्राधि. की वर्तमान नीति के अनुसार, भाराराप्राधि वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए दैनिक और मासिक असीमित पास एकल यात्रा दर के क्रमशः 1.5 गुना और 30 गुना की दर से प्रदान किए जाते हैं। तथापि यह सुविधा बीओटी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
- (ii) हमारे इस प्रश्न के उत्तर में कि असीमित यात्राओं के लिए पास हेतु प्रस्तावित दर की गणना हेतु हमारे आदेश में निर्धारित रियायती टोल स्थान पर एकल यात्राओं के लिए अनुमोदित अन्तरिम दर को आधार क्यों माना गया है, वीपीआरसीएल ने स्पष्ट किया है कि 15 दिसम्बर 2006 से 31 दिसम्बर 2006 तक लिए गए टोल डाटा के आधार पर प्रतिदिन अनेक फेरे लगाने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन औसतन 5 से 7 यात्राएं की जाती हैं। चूंकि प्रस्ताव प्रतिदिन औसतन 6 यात्राओं की तुलना में असीमित यात्रा अनुमत करने देने का है, प्रस्तावित दरों की गणना करते समय वापसी यात्रा और मासिक पास के लिए अन्यथा उपलब्ध रियायतों पर विचार नहीं किया गया है। इसने तर्क दिया है कि असीमित यात्रा करने देना अपने आप में एक रियायत है।
- (iii) इस समय, भा.रा.रा.प्राधि. ड्यूटी पर केन्द्रीय और राज्य सरकारी वाहनों को उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करता है। किन्तु इस नीति की समीक्षा की जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि इस छूट को वापिस लिया जा सकता है, तथापि इसने अनुरोध किया है कि भा.रा.रा.प्राधि. की नई नीति को लम्बित रखते हुए, ड्यूटी पर सरकारी वाहनों को इस लेवी से छूट प्रदान करने के इसके प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जाए।

5.5. असीमित पासों / असीमित यात्राओं के लिए पास हेतु वीपीआरसीएल से प्राप्त को वीपीटी को उसके विशिष्ट अभिमत के लिए भेजा गया था। वीपीटी ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और कहा है कि यात्राओं की संख्या पर पाबन्दी के बिना असीमित दैनिक और मासिक यात्राओं के लिए पास जारी करने का पतन उपयोगकर्ताओं का अनुरोध वाजिब है क्योंकि उन्हें दो टोल प्लाजाओं के बीच नियमित रूप से आना जाना है। इसने सूचित किया है कि वीपीआरसीएल के प्रस्ताव पर सम्बद्ध उपयोगकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया जिन्होंने, इस प्राधिकरण द्वारा अन्तिम दरें निर्धारित किए जाने तक अन्तरिम अवधि के लिए असीमित दैनिक / मासिक पासों हेतु तदर्थ टोल दरों से सहमति व्यक्त की है। अतएव, वीपीटी ने इस प्राधिकरण से प्रस्तावित दरों को अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसने यह भी निवेदन किया है कि वीपीआरसीएल बोर्ड ने (वीपीटी और भा.रा.रा.प्राधि. के प्रतिनिधियों से युक्त) ने ड्यूटी पर सरकारी वाहनों को छूट प्रदान करना वांछनीय माना है।

5.6. चूंकि वीपीटी ने वीपीआरसीएल के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था और उसने प्रस्तावित दरों को उचित पाया है और इस बात को स्वीकार करते हुए कि उपयोगकर्ताओं ने एक अन्तरिम अवधि के प्रस्तावित तदर्थ दरों के प्रति परस्पर सहमति व्यक्त कर दी है, इस प्राधिकरण ने, अन्तिम दरों के निर्धारण तक एक अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था के रूप में असीमित यात्राओं के लिए पास जारी करने हेतु प्रस्तावित तदर्थ दरों को अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश सं. टीएमपी /47/2006-वीपीआरसीएल दि. 12 जनवरी 2007 को पारित किया। सरकारी वाहनों को छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में, वीपीआरसीएल को, वाहनों की इस श्रेणी को छूट प्रदान करने के लिए भाराराप्राधि. द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण करने की सलाह दी गई थी क्योंकि सरकारी वाहनों को छूट प्रदान करने की भा.रा.रा.प्राधि. की नीति बीओटी

परियोजनाओं के लिए समीक्षा के अधीन है, इस प्राधिकरण द्वारा 12 फरवरी 2007 को पारित आदेश भारत का राजपत्र में 24 फरवरी 2007 को अधिसूचित किया गया था।

6.1. इस प्रकरण में, विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास परिसर में 12 जून 2007 को एक संयुक्त सुनवाई रखी गई थी। इस संयुक्त सुनवाई में विशाखापत्तनम् पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) ने परियोजना के विवरण को विस्तार से बताया है और टोल लगाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संयुक्त सुनवाई में वीपीआरसीएल और सम्बद्ध उपयोगकर्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे। संयुक्त सुनवाई में विशाखापत्तनम् स्टीवेजोर्स एसोसिएशन ने अपना पक्ष लिखित रूप में रखा।

6.2. जैसा कि संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया था, विशाखापत्तनम् पोर्ट कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) को ऐसे समुचित दस्तावेजों प्रमाण प्रस्तुत करने की सलाह दी गई जो यह सिद्ध करे कि वीपीआरसीएल द्वारा अपनायी गयी टोल संरचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अनुपालित, बीओटी परियोजनाओं के लिए प्रयोज्य राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है। वीपीआरसीएल को अपने पिछले प्रस्ताव में, टोल प्रभारों में वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने हेतु विवेचित संशोधित सूत्र को ध्यान में रखते हुए, परिवर्तन करने दिया गया था।

6.3. वीपीआरसीएल ने संयुक्त सुनवाई में उठाए गए बिन्दुओं का उत्तर दिया है, वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तुत मुख्य बातें, संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

- (i) यह सिद्ध करने के लिए कि वीपीआरसीएल द्वारा अपनाया गया प्रस्तावित टोल ढांचा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा, बीओटी परियोजनाओं के लिए अनुप्रयोज्य राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है, हमारे द्वारा मांगे गए दस्तावेजों समर्थन के संदर्भ में इसने राष्ट्रीय राजमार्ग-नियम 1997 की निम्नलिखित धारा 2 (राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग / स्थायी पुल / अस्थायी पुल के एक खंड के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क वसूल किए जाने का संदर्भ दिया है। "ऐसे समग्र खंड या उसके भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर होने वाले व्यय, निवेश की गई पूंजी पर ब्याज, समुचित आमदनी, यातायात की मात्रा और ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए शुल्क की दरें और वसूली की अवधि सुनिश्चित की जाएगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।"
- (ii) इसने टोल ढांचे पर संदर्भ के लिए समान परियोजनाओं से संबंधित, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित तीन अधिसूचनाओं, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर मुरादाबाद (18 जून 2001 को अधिसूचित), अहमदाबाद-बड़ोदरा द्रुतगति मार्ग (23 सितम्बर 2003 को अधिसूचित) और रा.राज. मार्ग-2 पर हुगली नदी के आरपार बने द्वितीय विवेकानंद सेतु (25 नवंबर 2005 को अधिसूचित) का संदर्भ दिया है।
- (iii) टोल से महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को प्रस्तावित राजस्व 6.12 करोड़ रुपये अपेक्षित था अर्थात् वर्ष 2006 में 1.68 लाख रुपये प्रतिदिन। किन्तु महा.प्र.प्राधि.द्वारा अनुमोदित तदर्थ दरों पर पिछले 6 माह के संग्रह के आधार पर टोल राजस्व रु. 95,000 /= प्रतिदिन ही हो पाया, जो अनुमानित टोल राजस्व से बहुत कम है। अतएव, टोल-राजस्व बढ़ाने के लिए यह वीपीटी से परामर्श कर रहा है।
- (iv) टोल प्रभारों में वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने हेतु सूत्र के बारे में इसने स्पष्ट किया है कि नई राष्ट्रीय राजमार्ग टोल नीति की विधि मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा कथित नीति अनुमोदित कर दिए जाने के तुरंत बाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध हैं। प्राप्त अभिमतों और संबद्ध पक्षों द्वारा रखे गए तर्कों का सारांश प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेज दिया जाएगा। ये ब्यौरे हमारे वेब साइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

8. इस प्रकरण पर कार्यवाई करने के दौरान संग्रहित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभर के आती है :-

- (i) विचाराधीन प्रस्ताव विशाखापत्तनम् पत्तन को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले इस प्रयोजन के लिए सृजित एक विशेष प्रयोजन निकाय विशाखापत्तनम् पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) द्वारा प्रचलित, नवनिर्मित जोड़ मार्ग / उड़्डान पुल के लिए टोल की अंतिम दरें निर्धारित करने हेतु है। चूंकि वीपीआरसीएल को महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 42 के अन्तर्गत वीपीटी द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है, इस प्राधिकरण के सामने प्रस्ताव प्रभार निर्धारित करने के लिए ही है।
- (ii) प्रस्तावित टोल पर, इस प्राधिकरण द्वारा तदर्थ अनुमोदन हेतु 17 नवंबर 2006 को उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में वीपीआरसीएल और वीपीटी के बीच विचार विमर्श हुआ था। विचार विमर्श का रिकार्ड किया विवरण सम्बद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा, प्रस्तावित दरों की तदर्थ आधार पर स्वीकृति की पुष्टि करता है। यहां तक कि वीपीटी ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।

चूंकि यह एक परस्पर स्वीकृत दर थी, प्रस्तावित टोल ढांचे को इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी / 47/2006-वीपीआरसीएल, जो 1 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित किया गया, छः माह की अंतरिम अवधि के लिए तदर्थ आधार पर अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात्, उन उपयोगकर्ताओं द्वारा जो बार-बार यात्रा करते थे प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, वीपीआरसीएल ने असीमित यात्राओं के लिए मासिक / दैनिक पास जारी करने के लिए अलग टोल प्रस्तावित किया था। चूंकि ये दरें भी सम्बद्ध उपयोगकर्ताओं के साथ परस्पर स्वीकृत दरें थी, और यह मानते हुए कि वीपीटी ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है, असीमित यात्राओं के लिए मासिक / दैनिक पास जारी करने हेतु अलग टोल, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी / 47/2006-वीपीआरसीएल के माध्यम से 24 फरवरी 2007 को अधिसूचित किया गया था।

- (iii) जैसाकि इससे पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस प्राधिकरण द्वारा तदर्थ आधार पर अनुमोदित प्रस्तावित टोल वीपीआरसीएल द्वारा, जोड़ मार्ग / उड़्डान पुल उपयोगकर्ताओं के लिए खोल दिए जाने के बाद 6 माह से भी अधिक समय से लगाया जा रहा है, विशाखापत्तनम् स्टीवेजोर्स एसोसिएशन (वीएसए) द्वारा सरसरी तौर पर की गई एक टिप्पणी के अलावा टोल ढांचे पर सम्बद्ध उपयोगकर्ताओं की ओर से कोई बिन्दुवार / तीखी अपत्ति नहीं आई है, सरसरी टिप्पणी भी यह है कि टोल ढांचा भा.रा.रा.प्राधि. की नीति के अनुरूप नहीं है। उसने अपने दावे की किसी दस्तावेजी सबूत के साथ पुष्टि नहीं की है। वीएसए ने इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित टोल की विशाखापत्तनम् में कुछ अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू टोल से तुलना की है।

परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए विशेष प्रयोजन निकाय (एसपीवी) को मान्यता देनी होगी अर्थात्, वीपीआरसीएल, भा.रा.रा.प्राधिकरण (एनएचआई) और वीपीटी के बीच संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी है और दोनों ही सरकार के अन्तर्गत सांविधिक प्राधिकरण हैं। प्रथम दृष्टया इस प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ये निकाय / संगठन सरकार की लागू नीति और अनुदेशों के विपरीत आचरण करेंगी।

वीपीआरसीएल ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भाग / राष्ट्रीय राज मार्ग पर बने स्थायी पुल / अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क की उगाही पर राष्ट्रीय राज मार्ग नियम, 1997 खंड-2 का संदर्भ दिया है, जो स्पष्ट करता है कि शुल्क की दरें और उगाही की अवधि का निर्णय ऐसे समग्र खंड या उसके किसी भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में आयी लागत, निवेशित पूंजी पर ब्याज, समुचित आमदनी, यातायात की मात्रा और ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। अन्य स्थानों पर, बीओटी आधार पर प्रचालित परियोजनाओं के लिए, वीपीआरसीएल द्वारा अग्रेषित, पोत परिवहन -सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय के तीन आदेश स्पष्ट करते हैं कि तीनों परियोजनाओं के लिए वाहन की एक विशेष श्रेणी हेतु प्रति किलो मीटर दर भिन्न है। यह अन्तर / भिन्नता निवेश के भिन्न स्तर, प्रचालन और अनुरक्षण लागत और यातायात में भिन्नता के कारण आयी होगी। इसलिए, वीएस द्वारा टोल की, की गई तुलना पूरी तरह प्रासंगिक नहीं पाई गई।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वीपीआरसीएल ने भा.रा.रा.प्राधि. द्वारा अपने जिम्मे ली गई यातायात अध्ययन की रिपोर्ट और प्रस्तावित टोल की विस्तृत गणना अग्रेषित कर दी है। सम्बद्ध उपयोगकर्ताओं के साथ एक बैठक में इसने इस बात की पुष्टि की है कि प्रस्तावित टोल ढांचा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नियमों पर आधारित है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण पहले अनुमोदित की गई तदर्थ दरों को अन्तिम दरों के रूप में अनुमोदित करना चाहता है।

- (iv) सूचित किया गया है कि टोल प्रभारों में वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने हेतु सूत्र को भा.रा.रा.प्राधि. द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। वीपीआरसीएल को, भा.रा.रा.प्राधि. द्वारा जब भी सूत्र (फार्मूला) अनुमोदित किया जाता है, टोल में वार्षिक वृद्धि लागू करने हेतु अलग प्रस्ताव लेकर आने की अनुमति दी गई है।
- (v) वीपीआरसीएल ने, टोल प्रभार लगाने से छूट दिए जाने के लिए व्यापक रूप से भाराराप्राधि के मागदर्शियों / नीतियों के आधार पर वाहनों की एक सूची प्रस्तावित की है।

तथापि, वीपीआरसीएल के आरम्भिक प्रस्ताव में डाक तार विभाग के वाहनों और ड्यूटी पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के वाहनों को टोल के भुगतान से छूट नहीं दी गई थी। विशाखापत्तनम में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों से तथा डाक-तार विभाग से ड्यूटी पर कार्यरत उनके वाहनों को टोल के भुगतान से मुक्ति प्रदान करने हेतु अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। ईस्ट नेवल कमांडबेस ने आवेदन दिया था कि सेनाओं और रक्षा बलों के सभी वाहनों को, फिर वो ड्यूटी पर हैं या नहीं, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार टोल के प्रभार से छूट दी जानी चाहिए।

राज्य / केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा रखी गई मांग को वीपीआरसीएल द्वारा भी वाजिब पाया गया है। अतएव, इसने ड्यूटी पर राज्य / केन्द्र सरकार के वाहनों को, भा.रा.रा.प्राधि. की संशोधित नीति को अन्तिम रूप दिए जाने तक टोल से मुक्त रखने पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग नियम 1997 (राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क की उगाही) और पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टोल संबंधी राजपत्र अधिसूचनाएँ ड्यूटी पर राज्य/केन्द्र सरकार के वाहनों को टोल प्रभार से छूट प्रदान करते हैं।

भा.रा.रा.प्राधि. नियमों में विशिष्ट स्थिति के मददे नज़र और समान परियोजनाओं के लिए पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आदेशों से प्राप्त स्थिति के आधार पर ड्यूटी पर राज्य / केन्द्र सरकार के वाहनों तथा रक्षा संबंधी वाहनों को टोल प्रभार से मुक्त रखने की आवश्यकता है। इन प्रविष्टियों को सम्मिलित करने के लिए, इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2006 के अपने आदेश द्वारा अधिसूचित, शुल्क-मुक्त वाहनों की सूची को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है। वीपीआरसीएल को सलाह दी जाती है कि वह वाहनों की विशिष्ट श्रेणी को टोल-प्रभार से छूट प्रदान करने के लिए भा.रा.रा.प्राधि. द्वारा अपनाई गई वर्तमान नीति का ही अनुसरण करे।

- (vi) छः माह की अन्तरिम अवधि के लिए इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त तदर्थ अनुमोदन पहले ही समाप्त हो गया है। अन्तिम दर के निर्धारण के अभाव में वीपीआरसीएल ने तदर्थ दरों को लगाना ही जारी रखा है। चूंकि अन्तिम दर पहले अनुमोदित तदर्थ दरों की पुष्टि मात्र ही है, अन्तिम दरों को विभिन्न आदेशों के क्रियान्वयन की तिथि के पिछले प्रभाव से प्रभावी हुआ मान लिया जाता है।

9. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से, तथा समग्र विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण 1 दिसम्बर 2006 और 24 फरवरी 2007 को अधिसूचित आदेशों के माध्यम से अनुमोदित तदर्थ टोल की अन्तिम दरों के रूप में, इस बारे में भाराराप्राधि की प्रचलित नीति के अनुसार छूट प्राप्त वाहनों की सूची में सुधार करने की शर्त पर, पुष्टि करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2007/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th August, 2007

No. TAMP/47/2006-VPRCL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal from the Visakhapatnam Port Road Company Limited (VPRCL) for fixation of toll for newly developed link road/flyovers connecting the Visakhapatnam Port to National Highway-5 as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/47/2006-VPRL

Visakhapatnam Port Road Company Limited**—Applicant****ORDER**

(Passed on this 7th day of August 2007)

This case relates to the proposal dated 8 November 2006 received from the Visakhapatnam Port Road Company Limited for fixation of toll for newly developed link road/flyovers connecting the Visakhapatnam Port to National Highway-5.

2.1. The National Highway Development Project (NHDP) Phase-I approved by the CCEA in December 2000, inter alia includes developing road connectivities to major ports. Under this programme, a port road connectivity project for developing connectivity from Visakhapatnam Port to National Highway-5 (NH-5) has been taken up by the National Highways Authority of India (NHAI). Accordingly, a Special Purpose Vehicle (SPV) namely Visakhapatnam Port Road Company Limited (VPRL) was incorporated under the Companies Act, 1956 on 26 December 2000 as a joint venture of Visakhapatnam Port Trust and NHAI.

2.2. The Visakhapatnam Port Trust (VPT) and VPRL signed a Concession Agreement on 8 November 2006 in order to implement the said port road connectivity project. As per the Concession Agreement, the VPRL shall undertake design, engineering, procurement, construction, operation and maintenance of the road connectivity with sole and exclusive right to demand/collect and appropriate fee (toll) from the users of the project.

2.3. The highlights of the proposal are as follows:

- (i). The road connectivity project commenced in June 2002 and is likely to be opened to traffic from December 2006.
- (ii). The port connectivity road project comprises of flyovers, ramps, roads at ground level, etc. of about 12.5 kms.
- (iii). The VPRL has stated that the total project cost has increased from Rs.93.8 crores as envisaged in the report prepared by IDFC to Rs.114 crores.
- (iv). The development of this project was envisaged with an objective to provide direct access for quick evacuation of the port traffic from the port area upto NH-5 and to have free traffic flow without hindrance due to road rail crossings and congestion of traffic experienced via existing roads connecting to NH-5. The said port connectivity facility is running within the city and industrial areas and will cater to the vehicular traffic of the public as well as the port cargo traffic.
- (v). M/s. IDFC, engaged as a financial advisor for the project, had submitted a report on financial viability of the project in 2003. They recommended toll rates at Rs.10/- for Car/Jeep/Van; Rs.20/- for LCV; Rs.40/- for Bus/Truck and Rs.60/- for MAV.
- (vi). The NHAI has also made a detailed traffic survey report on the port connectivity project and has suggested the toll structure alongwith detailed computation and report.

2.4. Accordingly, toll proposed to be levied by the VPRL is as follows:

- (i). Toll is proposed to be levied at the following two locations.
 - (a). Toll Plaza 1: Main toll plaza near Ayyapan Temple junction at NH-5.
 - (b). Toll Plaza 2: Secondary toll plaza on Industrial by-pass.

(ii). The proposed toll structure and concession proposed are tabulated below:

(a). Proposed toll:

Sl. No.	Type of Vehicle	(In Rs.)	
		Proposed Rates for main Toll Plaza	Proposed Rates for Secondary Toll Plaza
(i)	Car/Jeep/Van	9	5
(ii)	LCV	17	9
(iii)	Truck/Bus	33	18
(iv)	MAVs (3 to 6 Axles)/HCM/EME	54	28
(v)	Oversized Vehicles (7 or more Axles)	66	35

(b). Proposed concessions are:

Sl. No.	Pass	Concession
1.	Monthly	50 single journeys in a month with a discount of 1/3 of amount otherwise payable for 50 single journeys at Toll Plaza 1 and 2.
2.	Daily	Return journey in a day @ 1.50 times the rate of single journey at Toll Plaza 1 and two journeys per day at Toll Plaza 2 @ 1.5 times the rate of single journey.
3.	Local	Car/Jeep/Van local user i.e. resident within 20 km of the plaza @ monthly pass Rs.150/- per month.

(c). The following categories of vehicles are proposed to be exempted from the levy of the proposed toll:

- * Official vehicles transporting and accompanying the President of India, Vice President of India, Chief Justice of the Supreme Court, Union Minister, Governors, Lt. Governors, Chief Minister, Presiding Officers and Leaders of Opposition of the Central and State Legislatures, Judges of Supreme Court, Chief Justices of the High Courts, Ministers of States, Judges of the High Court and Foreign Dignitaries on State Visit;
- * Official vehicles of Central and State armed forces in uniform including paramilitary forces and police and of Executive Magistrates;
- * Member of Parliament in the entire country, Member of State Legislative Council and Member of State Assembly within their respective State when sitting in the vehicle, on production of identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
- * Vehicle belonging to winner of the Gallantry award such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;
- * Vehicles with CC/CD number plates;
- * Ambulances, fire tenders and funeral vans; and
- * Vehicles of persons using the highway for inspection, survey, construction, or operation and maintenance thereof.

Note: Posts and Telegraph Department vehicles and Central and State Government vehicles on duty will not qualify for treatment as exempted vehicles.

(iii). The toll proposed for the year 2006-07 is based on Wholesale Price Index (WPI) of December 2005 and the same are to be revised annually based on the WPI.

2.5. The VPRCL has also furnished the basis of arriving at the proposed toll. Based on the recent traffic studies it expects to generate revenue of Rs.6.12 crores during the year 2006-07 from levy of the proposed toll.

3.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of VPRCL alongwith the basis of calculation of the proposed toll structure was forwarded to the VPT and the concerned associations, public utility operators, major users including statutory authorities, seeking their comment.

3.2. The comments furnished by the concerned users were forwarded to the VPRCL for its comments as feedback information. The VPRCL has, however, not furnished its comments on the comments of the users so far.

4.1. While the case was taken on consultation, the VPRCL requested this Authority to approve the proposed toll since it planned to open the road connectivity project to traffic with effect from 1 December 2006. It had proposed some marginal adjustment in the toll structure proposed in its initial proposal. No modification was proposed in the exemption category of vehicles. The revised toll structure proposed by VPRCL is tabulated below

I. (A). Toll at Main Toll Plaza near Ayyappan Temple:

Sl. No.	Type of Vehicle	(In Rs.)	
		Single Journey Rate	Return Journey Rate, valid for 24 hours
1.	Car / Jeep / Van	10	15
2.	LCV	15	25
3.	Truck / Bus	35	55
4.	MAV (3 to 6 Axles) / HCM / EME	55	85
5.	Oversized Vehicles (7 or more Axles)	65	100

I. (B). Toll with concessions to local traffic / frequent travellers between Convent Junction and Ayyappan Temple on NH-5 (at main Toll Plaza near Ayyappan Temple).

Sl. No.	Pass	(In Rs.)				
		Car / Jeep / Van	LCV	Truck / Bus	MAV's (3 to 6 Axles) / HCM / EME	Over sized Vehicles (7 Axles or more)
1.	Monthly pass: (50 single journeys in a month with a discount of 1/3 rd of amount otherwise payable for 50 single journeys)	335	500	1165	1835	2165
2.	Daily pass (Return journey in a day @ 1.50 times the rate of single journey)	15	25	55	85	100
3.	Local pass for month: (For residents within 20 KM of the toll plaza on production of residence proof and ownership proof of vehicle)	150	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

3524 45167-4

II. (A). Toll for Secondary Toll Plaza near 'Y' Junction.

Sl. No.	Type of Vehicle	(In Rs.)	
		Single Journey Rate	Return Journey Rate, valid for 24 hours
1.	Car / Jeep / Van	5	10
2.	LCV	10	15
3.	Truck / Bus	20	30
4.	MAV (3 to 6 Axles) / HCM / EME	30	45
5.	Oversized Vehicles (7 or more Axles)	35	55

II. (B). Toll with concessions to local traffic / frequent travellers between Convent Junction and 'Y' Junction (at Secondary Toll Plaza near 'Y' Junction).

Sl. No.	Pass	(In Rs.)				
		Car / Jeep / Van	LCV	Truck / Bus	MAV's (3 to 6 Axles) / HCM / EME	Over sized Vehicles (7 Axles or more)
1.	Monthly pass: (50 single journeys in a month with a discount of 1/3 rd of amount otherwise payable for 50 single journeys)	165	335	665	1000	1165
2.	Daily pass: (Two journeys in a day @ 1.50 times the rate of single journey)	10	15	30	45	55
3.	Local pass for month: (For residents within 20 KM of the toll plaza on production of residence proof and ownership proof of vehicle)	150	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

4.2. The VPT and VPRCL held discussion regarding the toll to be levied on *ad hoc* basis with the relevant users in the meeting convened by them on 17 November 2006. The record note of discussions held on 17 November 2006, which was furnished by VPRCL, indicated that the relevant users had accepted the proposed rates to be levied on an *ad hoc* basis till fixation of final rates by the Authority.

4.3. Since the project was proposed to be opened for traffic with effect from 1 December 2006, it was necessary for a tariff arrangement to be in place to enable the VPRCL to operate the facilities. As the proposed *ad hoc* rates were mutually agreed rates, this Authority passed an Order No. TAMP/47/2006-VPRCL on 28 November 2006 approving the proposed *ad hoc* rates as an interim arrangement for a period of six months. This Order was notified on 1 December 2006 in the Gazette of India vide Gazette No. 177.

5.1. Subsequently, the VPRCL pointed out the difficulties expressed by the users with reference to the *ad hoc* monthly pass system approved by this Authority. The VPRCL pointed out that the passes were exhausted within a very short period of 4 to 5 days as many of the users had to make number of trips in a day. The monthly pass issued with 50 limited journeys was not found adequate for a full month. In view of the difficulties expressed by the port users, the VPT had advised the VPRCL to issue passes for unlimited journeys. The VPT had also advised the VPRCL to exempt toll fee for the Government vehicles on duty.

5.2. In this backdrop, the VPRCL has proposed to introduce separate rates for daily / monthly passes for unlimited journeys. The existing ad hoc rate approved for single journey is taken as the base and applied for six journeys for arriving at the proposed rate for daily pass for unlimited journeys. Likewise, for monthly pass the same factor was applied for 30 days per month. Accordingly, the toll structure proposed by VPRCL for issue of passes for unlimited journeys is tabulated below:

At Main Toll Plaza near Ayyappa temple

(In Rs.)					
Pass	Car / Jeep / Van	LCV	Truck / Bus	MAV's (3 to 6 Axles) / HCM / EME	Over sized Vehicles (7 Axles or more)
Daily Pass (Unlimited journeys)	60	90	210	330	390
Monthly Pass (Unlimited journeys)	1800	2700	6300	9900	11700

At Secondary Toll Plaza near 'Y' Junction

(In Rs.)						
Sl. No.	Pass	Car / Jeep / Van	LCV	Truck / Bus	MAV's (3 to 6 Axles) / HCM / EME	Over sized Vehicles (7 Axles or more)
4(a).	Daily Pass (Unlimited journeys)	30	60	120	180	210
4(b).	Monthly Pass (Unlimited journeys)	900	1800	3600	5400	6300

5.3. In addition to the existing list of exempted categories of vehicles, the VPRCL proposed to exempt the Government vehicles on duty from levy of toll till such time the revised policy of NHAI comes into force. It has also pointed out that at secondary toll plaza, the daily pass is for two journeys instead of return journey mentioned in the interim tariff notified on 1 December 2006 and hence the description needs to be corrected accordingly.

5.4. With reference to its proposal for issue of passes for unlimited journeys, the VPRCL was requested to furnish additional information/clarification on some of the points. Clarifications furnished by VPRCL is summarised below:

- (i). As per the existing policy of NHAI, daily and monthly unlimited passes are provided at 1.5 and 30 times the single rate for NHAI funded projects. This facility, however, is not available for BOT projects. The policy is under review.
- (ii). With reference to our query as to why the interim rate approved for single journey is considered as the base for arriving at the proposed rate for unlimited passes instead of concessional toll prescribed in our Order, the VPRCL has clarified that average number of journeys by the users making multiple trips per day is 5 to 7 based on the toll data collected from 15 December 2006 to 31 December 2006. Since it is proposed to allow unlimited journeys as against the average number of 6 journeys per day, the concessions otherwise available for return journey and monthly pass are not considered for arriving at the proposed rates. It has argued that allowing unlimited journeys in itself is a concession.
- (iii). At present, NHAI exempts Central and State Government vehicles on duty from payment of the user fees. But, this policy is under review and it is anticipated that this exemption may be withdrawn. It has, however, requested to approve its proposal for exempting Government vehicles on duty from this levy pending implementation of the new policy of NHAI.

5.5. The proposal received from the VPRCL for issue of passes for unlimited journeys was forwarded to the VPT for its specific comments. The VPT has endorsed the proposal and stated that the request of the port users for issue of unlimited daily and monthly journeys without ceiling on the number of journey is genuine, as they have to regularly operate between the two toll plazas. It has reported that the proposal of VPRCL was discussed with the concerned users who have agreed to the proposed ad

33244567-5

the proposal of VPRCL was discussed with the concerned users who have agreed to the proposed ad hoc toll rates for unlimited daily/monthly passes for interim period till fixation of final rates by this Authority. The VPT has, therefore, requested this Authority to accord approval to the proposed rates. It has also submitted that the VPRCL Board (comprising of VPT and NHA representatives) considered it desirable to exempt Government vehicles on duty.

5.6. Since, the VPT had endorsed the proposal of the VPRCL and had found the proposed rates to be justified and also recognising that the users had mutually agreed to the proposed ad hoc rates for an interim period, this Authority passed an Order No. TAMP/47/2006-VPRCL on 12 February 2007 approving the ad hoc rates proposed by the VPRCL for issue of passes for unlimited journeys as an interim tariff arrangement till fixation of the final rates. With regard to exemption of Government vehicles, the VPRCL was advised to continue to follow the policy adopted by the NHA for exempting this category of vehicle since the NHA policy for exemption of Government vehicles is under review for BOT projects. The Order passed by this Authority on 12 February 2007 was notified in the Gazette of India on 24 February 2007.

6.1. A joint hearing, in this case was held on 12 June 2007 at the Visakhapatnam Port Trust premises. At the joint hearing, the Visakhapatnam Port Road Company Limited (VPRCL) explained the project details and presented its proposal for levy of toll. At the joint hearing, VPRCL, and the concerned users made their submissions. The Visakhapatnam Stevedores Association filed written submissions at the joint hearing.

6.2. As decided in the joint hearing, the Visakhapatnam Port Road Company Limited (VPRCL) was advised to furnish relevant documentary support to substantiate that the proposed toll structure adopted by the VPRCL is in line with the national policy followed by the National Highway Authority of India (NHA) applicable for BOT projects. The VPRCL was also allowed to amend its earlier proposal in view of revised formula contemplated by the Government for determining the annual escalation in toll charges.

6.3. The VPRCL has responded to the points made at the joint hearing. The main submissions made by the VPRCL are summarised below:

- (i). With reference to documentary support sought by us to substantiate that the proposed toll structure adopted by the VPRCL is in line with the national policy followed by the National Highway Authority of India (NHA) applicable for BOT projects, it has referred to the following clause 2 of the National Highways (Collection of Fees by any Person for use of section of National Highway/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997:

"The rates of fees and the period of collection shall be decided and shall be specified by notification in the Official Gazette by the Central Government having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the whole or part of such section, interest on the capital invested, reasonable return the volume of traffic and the period of such agreement".

- (ii). It has given reference of three notifications published by the Ministry of Road Transport and Highways in the Gazette of India on toll structure at Moradabad Bypass on NH-24 (notified on 18 June 2001), Ahmedabad-Vadodra Expressway (notified on 23 September 2004) and 2nd Vivekananda Bridge across river Hooghly on NH-2 (notified on 25 November 2005) pertaining to similar projects for reference.
- (iii). The revenue from the toll proposed to TAMP was expected to be around Rs.6.12 crores i.e. a toll revenue @ Rs. 1.68 lakhs per day in the year 2006. However, the toll revenue based on last 6 months collection at adhoc rates approved by TAMP is only 95,900/- per day which is far less than the estimated toll revenue. It is, therefore, having consultation with the VPT for augmenting the toll revenue.
- (iv). As regards the formula for determining the annual escalation for toll charges, it has clarified that the new National Highway Toll Policy is under vetting by Ministry of Law. A proposal will be submitted soon after said Policy is approved by the Central Government.

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>

8. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal under consideration is for fixation of final rates for the newly developed link road/ flyover connecting the Visakhapatnam Port to National Highway operated by a Special Purpose Vehicle created for this purpose i.e. Visakhapatnam Port Road Company Limited (VPRCL). The proposal before this Authority is for fixing the charges since VPRCL is offered the Licence by VPT under Section 42 of the Major Port Trusts Act 1963.
- (ii). The proposed toll was discussed by the VPRCL with the VPT and the relevant users in the meeting convened by them on 17 November 2006 for adhoc approval by this Authority. The record note of discussions confirms acceptance of the proposed rates by the concerned users on an adhoc basis. Even the VPT has endorsed the proposal.

Since it was a mutually agreed rate, proposed toll structure was approved by this Authority on an adhoc basis for an interim period of six months vide Order No. TAMP/47/2006-VPRCL notified on 1 December 2006.

Subsequently, based on representations made by the users who are frequent travellers, the VPRCL had proposed separate toll for issue of monthly / daily passes for unlimited journeys. Since these rates were also mutually agreed rates with the concerned users and recognising that the VPT had endorsed the proposal, separate toll for issue of monthly/ daily passes for unlimited journeys was notified by this Authority vide Order No. TAMP/47/2006-VPRCL notified on 24 February 2007.

- (iii). As already mentioned earlier, the proposed toll approved by this Authority on adhoc basis is being levied by the VPRCL for more than six months after opening the road/ flyover to users. There have not been any pointed objections from the concerned users on the toll structure except a general remark made by the Visakhapatnam Stevedores Association (VSA) that the toll structure is not as per the policy of the NHAI. It has not substantiated its claim with any documentary support. The VSA has made a comparison of the proposed toll with the toll applicable at some other National Highway at the Visakhapatnam for this purpose.

It has to be recognised the SPV set up to execute the project i.e. VPRCL is a joint venture company between NHAI and VPT, both of which are statutory authorities under the Government. Prima facie, this Authority does not have any reasons to believe that these bodies would have acted in any manner contradictory to the applicable Governmental policy and instructions.

The VPRCL has referred to clause 2 of the National Highways Rules, 1997 on Collection of Fees by any Person for use of section of National Highway/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways which clarifies that the rates of fees and the period of collection shall be decided having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the whole or part of such section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of such agreement.

The three Orders of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways for similar projects operated on BOT basis at other places forwarded by VPRCL reveal that the rate per km for a particular category of vehicle is different for the three projects. The difference may have arisen due to different level of investment, operations and maintenance cost and traffic. Hence the comparison of toll made by the VSA is not found to be fully relevant.

It is significant to mention that the VPRCL has forwarded the report of traffic study and detailed computation of proposed toll undertaken by the NHAI. It has in a meeting with concerned users confirmed that the proposed toll structure is based on the NHAI rules.

In view of this position, this Authority is inclined to approve the adhoc rate approved earlier as the final rate.

- (iv). It is reported that the formula for determining annual escalation in the toll charges is being finalised by the NHAI. The VPRCL is allowed to come up with a separate proposal for application of annual escalation in toll as and when the formula is approved by the NHAI.
- (v). The VPRCL has proposed a list of vehicles to be exempted from levy of the toll broadly based on the guidelines / policies of the NHAI.

The initial proposal of the VPRCL, however, did not exempt Post and Telegraph vehicles and Central and State Government vehicles on duty from levy of toll. Several representations were received from Central / State Government offices in Visakhapatnam and Department of Post and Telegraph to exempt their vehicles on duty from levy of toll. The East Naval Command Base has submitted that all military and defence vehicles irrespective of whether they are on duty or not must be exempted from levy of toll in accordance with the directions from the Ministry of Transport and Highways.

The VPRCL has also found the demand made by the State / Central Government offices to be relevant. It has, therefore, agreed to exempt the State / Central Government Vehicles on duty from levy of toll till the revised policy of the NHAI is finalised.

The National Highway Rules 1997 (Collection of Fees by any Person for use of section of National Highway/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways), and Gazette Notifications of toll approved by the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways exempts State/ Central Government vehicles on duty and defence vehicles from levy of toll.

In view of specific position in the NHAI Rules and also based on the position obtained from the Orders notified by the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways for similar projects, the State / Central Government Vehicles on duty and defence vehicles need to be exempted from levy of toll. The list of exempted vehicles notified by this Authority vide Order dated 28 November 2006 needs to be suitably modified to include these entries.

The VPRCL is advised to follow the prevailing policy adopted by the NHAI for exempting the specific categories of vehicles from levy of toll.

- (vi). The adhoc approval granted by this Authority for an interim period of six months has already expired on 1 June 2007. The VPRCL continues to levy the adhoc rate in the absence of fixation of final rate. Since the final rate is only a confirmation of the adhoc rates approved earlier, the final rates is deemed to have come into effect retrospectively from the date of implementation of the respective Orders.

9. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority confirms the adhoc toll approved vide Orders notified on 1 December 2006 and 24 February 2007 as the final rate subject to modification in the list of exempted category of vehicles as per the prevailing NHAI policy in this regard.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/N/143/2007/Ext.]